#### राजस्थान सरकार कार्मिक (ख-3) विभाग

क्रमांक - एफ.7(04)/कार्मिक/ख-3/2017

जयपुर,: दिनांक

## ई-निविदा सूचना

शासन सचिवालय जयपुर के विभिन्न विभागों, अनुभागों, मंत्रीगणों के कार्यालय, आयोग, लोकायुक्त सचिवालय एवं बोर्ड के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 (दिनांक-01;03;2017 से 30;09;2017 तक या किनष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों पर नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हों) में 176 कम्प्यूटर मय दक्ष ऑपरेटर किराये पर लेने हेतु निर्धारित प्रपत्र में E-Procurement प्रक्रिया के तहत केवल www.eproc.rajasthan.gov.in की ऑन लाईन निविदा के माध्यम से निविदा निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है ।

क्र0सं0	विवरण	विस्तृत विवरण
1	कार्य का विवरण	शासन सचिवालय जयपुर के विभिन्न विभागो, अनुभागों,
		मंत्रीगणों के कार्यालय, आयोग, लोकायुक्त सचिवालय एवं बोर्ड
		के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 (दिनांक-01;05;2017 से
		30;09;2017 तक या किनष्ठ लिपिको के रिक्त पदों पर
		नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो) में 176
		कम्प्यूटर मय ऑपरेटर किराये पर लेने हेतु
2	निविदा की अनुमानित लागत	प्रति वर्ष 75.00 लाख रूपये
3	प्रतिभूति बोली राशि	01.50 लाख रुपये संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख) विभाग
		शासन सचिवालय, जयपुर के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट बना हुआ
		हो ।
4	निविदा प्रपत्र शुल्क	1000.00 रुपये संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख) विभाग
		शासन सचिवालय, जयपुर के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट बना हुआ
		हो ।
5	RISL प्रसंस्करण शुल्क	1000.00 रुपये प्रबन्ध निदेशक, RISL, जयपुर के नाम से
		डिमाण्ड ड्राफ्ट बना हुआ हो ।
6	निविदा आमंत्रितकर्ता	संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख) विभाग, शासन
		सचिवालय, जयपुर
7	निविदा प्रपत्र को अपलोड करने की दिनांक एवं समय	09/03/2017 को सायं 3.00 बजे
8	निविदा प्रपत्र को डाउन लोड करने के शुरू होने का दिनांक	09/03/2017 को सायं 04:00 बजे
	एवं समय	
9	बोली प्रस्तुत प्रारंभ होने की तिथि व समय	09/03/2017 को सायं 6.00 बजे
10	निविदा प्रपत्र डाउनलोड समाप्ति तिथि व समय	08/04/2017 को सायं 06:00 बजे
11	निविदा प्रस्तुत करने के अन्तिम तिथि व समय	09/04/2017 को सायं 4.00 बजे
12	निविदा प्रपत्र शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि के	10/04/2017 को प्रात- 11;00 बजे
	डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने की तिथि व समय	
13	तकनीकी निविदा खुलने की तिथि व समय	10/04/2017 को सायं 3.00 बजे
14	वित्तीय बोली खोलने की तिथि व समय	तकनीकी रूप से योग्य बोली दाताओं को सूचित कर दिया
		जावेगा
15	अनुबंध की अवधि	(दिनांक-01;05;2017 से 30;09;2017 तक या कनिष्ठ लिपिको
		के रिक्त पदों पर नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी
		पहले हो)

- इच्छुक बोलीदाताओं को बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नामांकित / www.eproc.rajasthan.gov.in के पोर्टल के साथ पंजीकृत होना होगा
- 2. यदि किसी कारणवश अवकाश रहता है तो उसके अगले दिन उसी समय पर निविदा खोली जावेगी।
- 3. निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट www.dop.rajasthan.gov.in, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की वेबसाईट www.dipr.rajasthan.gov.in एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.raj.nic.in पर देखे जा सकते है ।

संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर

# किराये पर लिये जाने वाले कम्प्यूटर मय ऑपरेटर का विवरण

क्र0स0	लगाये जाने वाले कम्प्यूटर का कान्फिग्रेशन	ऑपरेटर की योग्यता
1.	Computer- Intel Core i3/Equivalent AMD based Computer or higher speed, RAM 2/4GB or higher, Hard disk 250 GB or more, 15"Monitor/TFT or bigger,10/100/1000Mbps LAN Card, CD/DVD Writer, Standard keyboad, optical, Mouse, Standard Serial, Parallel & USB ports Windows 7 or higher, AntiVirus Preinstalles MS Office. Responsibility of software license will be borne by the contractor.  Printer- Black and white laser printer with speed 15 ppm or more. For specific needs, /inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.  UPS- Online/offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.	Operator should be graduate having knowledge to operate computer in Windows with good of World Processor, Spread Sheets and Internet Operations and other office related computer operations and should have sufficient speed of hindi typing in Hindi and English

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

- 1. निविदादाता का नाम
- 2. डाक का पता
- 3. टेलीफोन नम्बर (दुकान) (घर)

जयपुर, दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

#### <u>एनेक्सर-एच</u>

# 'Financial Tender Form'

Tender Document for

शासन सचिवालय में कम्प्यूटर मय ऑपरेटर किराये पर लिये जाने का अनुबन्ध हेतु ।

Ref. NIT No. F-7 (4)DOP/B-III/2017 Jaipur, dated 09/03/2017

Tender Inviting Authority: J.S. DOP (B), Government Secretariat, Jaipur, Rajasthan		
Name of Work : शासन सचिवालय जयपुर में कम्प्यूटर मय दक्ष ऑपरेटर किराये पर लिये जाने की दर संविदा ।		
Contract No: Ref. NIT No. F-7 (04)DOP/B-III/2017 Jaipur, dated 09/03/2017		
Bidder Name :		
SCHEDULE OF WORKS		

	Total Table 1
लगाये जाने वाले कम्प्यूटर का कान्फिग्रेशन	प्रतिमाह कुल दर प्रति कम्पूयटर मय ऑपरेटर (सभी करों
	सहित ) अंको व शब्दों में
Computer- Intel Core i3/Equivalent AMD based Computer or higher speed, RAM 2/4GB	
or higher, Hard disk 250 GB or more, 15"Monitor/TFT or bigger,10/100/1000Mbps LAN	
Card, CD/DVD Writer, Standard keyboad, optical, Mouse, Standard Serial, Parallel & USB	
ports Windows 7 or higher, AntiVirus Preinstalles MS Office.Responsibility of software	
license will be borne by the contractor.	
<u>Printer</u> - Black and white laser printer with speed 15 ppm or more. For specific needs,	
inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.	
<u>UPS-</u> Online/offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.	

- 1. निविदादाता का नाम
- 2. डाक का पता
- 3. टेलीफोन नं. (दुकान) (घर) जयपुर,दिनांक

# तकनीकी निविदा प्रपत्र

शासन सचिवालय जयपुर के विभिन्न विभागो, अनुभागों, मंत्रीगणों के कार्यालय, आयोग, लोकायुक्त सचिवालय एवं बोर्ड के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 (दिनांक-01.05.2017 से 30.09.2017 तक या कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों पर नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो) में 176 कम्प्यूटर मय दक्ष ऑपरेटर किराये पर लेने हेतु तकनीकी निविदा प्रपत्र।

1	बोली/दर संविदा आमंत्रित करने		कार्मिक (ख-3	८) विभाग, श	ासन सचिवालय	
2	बोली/दर संविदा का संदर्भ		बोली/दर संविदा सूचना क्रमांकः प 7(4)कार्मिक-ख/3/2017			
			दिनांक 09/03/2017			
3	बोली/दर संविदा अधीन कार्य का वि	वरण	कम्प्यूटर मय	ऑपरेटर के	लिए बोली/दर संविदा	I
4	बोली/दर संविदा प्राप्त करने वाले अ	धिकारी नाम	संयुक्त शासन	न सचिव,विभा	ाग (ख) कार्मिक ,शासन	सचिवालयजयपुर
6	ऑन लाईन बोली/दर संविदा प्रस्त	नुत करने के	दिनांक 09/04	4/2017 को	प्तायं 4.00 बजे तक	
	अन्तिम तिथि व सम	म				
7	तकनीकी बोली/दर संविदा खुलने की	तिथि और	दिनांक 10/04	4/2017 को	सायं 3.00 बजे तक व	को उपस्थित बोली/दर
	समय		संविदा या उ	नके प्रतिनिधि	ोयो की उपस्थिति में ः	संयुक्त शासन सचिव
		T	कार्मिक (ख)	विभाग के क	गर्यालय में खोली जावेर्ग	ÌΙ
8	बोली/दर संविदा का विवरण	ना	म			
		पता				
		टेलीफोन				
		मोबाइल फोन	Γ			
		प्राधिकृत र्व्या	क्त का			
		नामपदनाम/				
9	बोली/दर संविदा शुल्क राशि 100	0.00 /- डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चै		/बैंकर चैक	क संख्या	
	रूपये जमा कराने का विवरण	कराने का विवरण				
10	बोली/दर संविदा प्रसंकरण शुल्क	राशि1000/-	डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या			
	रूपये का जमा करवाये जाने का विवरण		दिनांक			
11	बोली प्रतिभूति राशि 01.50 /-ल	ख रूपये	डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या			
	जमा कराने का विवरण		दिनांक			
12	गत एक वर्ष में राजकीय वर्ष	ি	। वेभाग नाम		कार्य की राशि	अपेक्षित दस्तावेज
	विभागो/संस्थाओं में					संलग्न करें।
	कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के कार्य अनुभव का विवरण 2015-16	3				(पृष्ठ संख्या)
	-			1	<u> </u>	
13	आयकर पैन (PAN) नम्बर				प्रमाणपत्र संलग्न करे	
	पैन कार्ड की छाया प्रति				पृष्ठ सखंया	
14	सर्विस कर पंजीयन प्रमाण-पत्र				प्रमाणपत्र संलग्न करे	-
14	্ নাপ্র কং শ্রাপ্ত স্লাশ-প্র					
					पृष्ठ सखंया	

15	फर्म द्वारा वित्तीय 2015-16 में	बिक्री/टर्नओवर की राशि रूपये	लेखे संलग्न करे
	बिक्री/ टर्नओवर रूपये 20/- लाख		पृष्ठ सख्या
	होना आवश्यक है		
	होना आवश्यक है		

- 16. (क) किराये पर लिये जाने वाले कम्प्यूटर मय ऑपरेटर का स्पेसिफिकेशान/योग्यता संलग्न एनेक्सर ई के अनुसार है।
  - (ख) कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की किराये की दर अलग से वित्तीय निविदा प्रपत्र में अंकित की गई है उक्त वित्तीय निविदा पत्र को अलग से वित्तीय निविदा के लिफाफे में बन्द किया गया है।
- 17. आदेश प्राप्ती की दिनांक से 10 दिवस की अवधि के भीतर फर्म द्वारा विभाग को कम्प्यूटर मय ऑपरेटर उपलब्ध कराने होगे। इसमें देरी पर रूपये 300.00 प्रतिदिन प्रति कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के हिसाब से पेन्न्टि लगायी जावेगी।
- 18. अनुमोदित दर संविदा दरें 01.05.2017 से 30.09.2017 (या किनष्ठ लिपिको के रिक्त पदों पर नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो) की अविध के लिए विधिमान्य होगी। इस अविध को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम- 2013 के अनुसार बढ़ाया भी जा सकेगा।
- 19. अनुमोदित दर संविदा दरों पर कार्मिक विभाग द्वारा कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की सेवाये वित्तीय वर्ष् 2017-18 के दौरान विभागीय आवश्यकता के अनुसार ली जा सकेगी। कार्य की अविध व संख्या मांग के अनुसार पिरवर्तनीय रहेगी।
- 21. निविदा स्वीकार किये जाने पर पाँच प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।
- 22. बोली/दर संविदा में अनुमोदित दरें कार्यआदेश दिये जाने से 01.05.2017 से 30.09.2017 (या किनष्ठ लिपिको के रिक्त पदों पर नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो) तक की अविध के लिये विधिमान्य होगी दरों को राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम -29 एवं 73 के अनुसार बढाई जा सकेगी।
- 23. निविदा स्वीकार करने या नहीं करने का पूर्ण अधिकार विभाग के पास होगा।

बोलीदाता/संविदादाता के हस्ताक्षर	
दिनांक	
ठेकेदार/संस्था का नाम	
संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम व पदनाम	
दूरभाष संख्या (कोइ सहित)	
मोबाइल फोन नम्बर	
ई-मेल पता	

# राजस्थान सरकार कार्मिक (ख-3) विभाग

क्रमांक एफ- प0 7(04)कार्मिक/ख-3/2017

### निविदा प्रपत्र

जयप्र : दिनांक 09.03.2017

शासन सचिवालय जयपुर के विभिन्न विभागो, अनुभागों, मंत्रीगणों के कार्यालय, आयोग, लोकायुक्त सचिवालय एवं बोर्ड के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 (दिनांक-01.05.2017 से 30.09.2017 तक या किनष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों पर नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो) में 176 कम्प्यूटर मय दक्ष ऑपरेटर किराये पर लेने हेतु दर संविदा

ऑन लाईन दर संविदा प्रस्तुत करने की	08-04-2017 को सायं 04.00 बजे तक
अन्तिम तिथि एवं समय :	
तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय:	10-04-2017 सायं 03:00 बजे
ऑन लाईन बोली खोलने का स्थान :	कक्ष संख्या 7008 खाद्य भवन, शासन
	सचिवालय, जयपुर ।

निविदा शुल्क राशि 1000/- (अक्षरे रूपये एक हजार मात्र)

ई-निविदा प्रसंस्करण शुल्क Rs. 1000/- (अक्षरे रूपये एक हजार मात्र)

बोलीदाता फर्म का नाम:	
अधिकृत व्यक्ति जिससे सम्पर्क किया जा सके (प्राधिकृत बोली हस्ताक्षरी):	
पत्राचार का पता:	
मोबईल नम्बर :	टेलीफोन एवं फैक्स नम्बर:
वेबसाईट एवं ईमेल:	

## अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु : -

- 1. कार्मिक (ख—3) विभाग, शासन सचिवालय,1 शासन सचिवालय में मेन विद मशीन के कार्य के लिए दर संविदा हेतु बोलीदाताओं को वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए. निविदा प्रथम भाग में तकनीकी बोली प्रस्ताव एवं द्वितीय भाग वित्तीय बोली प्रस्ताव होगें।
- 2. बोलीदाताओं ई-निविदा प्रक्रिया को समझने के लिए वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से भरे जाने के लिए और कड़ी "ठेकेदार के लिए मदद", "डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र) के बारे में जानकारी", "पूछे जाने वाले प्रश्न" का उल्लेख है और चाहिए "बोलीदाताओं मैनुअल किट 'और वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक बोलियां प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया का पता करने के लिए बिन्द संख्या 8 देखें ।
- 3. बोलीदाताओं एक वर्ग 2 या ई निविदा पोर्टल के लिए एक लाइसेंस प्राप्त प्रमाणन प्राधिकरण (सीए) द्वारा जारी वर्ग 3 श्रेणी के डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता है.
- 4. पूरा बोली दस्तावेज डाउनलोड करने के प्रयोजन के लिए वेबसाइटों http://dop.rajasthan.gov.in और ttp://eproc.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित किया गया है. डाउनलोड की अंतिम बोली दस्तावेज में केवल 1,000 रुपये का ई टेंडर प्रक्रिया का प्रसंकरण शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक प्रबंध निदेशक, RISL, जयपुर के नाम से देय हो संलग्न कर प्रस्तुत करने पर बोली की प्रक्रिया के में भाग लेने के लिए वैध माना जाएगा । निविदा प्रपत्र शुल्क 1000 / नकद जमा करवाई जा सकती है या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पक्ष में देय हो प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
- 5. बोली दस्तावेज (तकनीकी और वित्तीय बोली) सिहत सभी संचार / पत्राचार बोलीदाता के नामित अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए ।
- 6. तकनीकी बोली निविदा सूचना में और बोली लगाने के नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा सूचना में अंकित दिनांक के अनुसार खोला जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया की योग्यता बोलियां पूर्ण करने पर ही वित्तीय निविदा के मूल्यांकन के लिए आगे विचार किया जाएगा। वित्तीय बोली हेतु सभी तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों को बाद में सूचित किया जाएगा जो अलग तारीख और समय पर तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं / नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी।
- 7. बोलीदाताओं को बोली प्रतिभूति राशि, निविदा शुल्क, और ई-टेंडर प्रक्रिया शुल्क राशि के डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक एवं ई-निविदा प्रपत्र (केवल तकनीकी निविदा) की हार्डकॉफी दिनांक 10/03/2017 को प्रात- 11;00 बजे तक पंजीयक शासन सचिवालय, जयप्र के कक्ष में जमा करवानी होगी
- 8. **ई-निविदा से संबंधित बिन्दु** (क) बोलीदाता ई उपापन की बेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in को देखें एवं बोली के लिए पंजीकरण और ई निविदा प्रस्तुत करने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने होगा ।
- (ख) बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख के पहले अच्छी तरह से अपनी बोली प्रस्तुत करना चाहिए कार्मिक विभाग आखिरी समय पर प्रस्तुत करने के दौरान बोलीदाता को पेश करने में आ रही किसी भी समस्या के लिए उत्तरदायी नहीं होगा एवं समय सीमा / वेबसाइट पर प्रस्तुत नहीं की गई बोलियों को शामिल करने के लिए अनुमित का विस्तार से उपरोक्त कारणों की वजह से विचार नहीं किया जाएगा ।
- (ग) बोलीदाताओं को बेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in/ पर रजिस्टर और ई-टेंडर के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा । बोली ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी । ऑफ़लाइन प्रस्तुत बोलियों के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया किया जावेगा और खारिज कर दिया जाएगा ।
- (घ) वित्तीय बोली के लिए, बोलीदाताओं बोली के एक भाग के रूप में वेबसाइट पर अपलोड BoQ.XLS (माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ़ाइल) डाउनलोड करना चाहिए और टेम्पलेट के लिए किसी भी संशोधन के बिना विवरण भरें जबिक अपलोड ई) डाउनलोड BoQ.XLS (माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ़ाइल) में किए गए छेड़छाड़ / परिवर्तन प्रारूप वेबसाइट दवारा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
- (च) बोलीदाता ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक वैध वर्ग 2 या वर्ग 3 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की जरूरत है ।
- (छ) बोलीदाता अपनी बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तृत सभी दस्तावेजों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने आवश्यक है ।
- (ज) कार्मिक विभाग गैर अन्पालन के मामले में ई टेंडरिंग प्रक्रिया के लिए बोलियों की अस्वीकृति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- (झ) बोलीदाताओं को सभी आवश्यक दस्तावेज जो निविदा दस्तावेज में उल्लेख किया है अपलोड करने की जरूरत है ।
- (य) यदि कोई शुद्धिपत्र वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा, वह इस बोली का एक हिस्सा होगा बोलीदाताओं को बोली से संबंधित अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से इस वेबसाइट को देखना चाहिए ।

- (र) बोलियां को ऑनलाइन खोला जाएगा । बोलीदाता कार्मिक (ख-3) विभाग में बोली ऑन लाईन खोलते समय उपस्थित हो सकते हैं ।
- (ल) बोलीदाताओं उनकी बोली प्रतिभूतिराशि, निविदा दस्तावेज शुल्क और ई टेंडर प्रक्रिया शुल्क प्रस्तुत करना चाहिए ।
- (व) बोलीदाताओं को सावधान रहना चाहिए । तकनीकी बोली से संबंधित दस्तावेज केवल तकनीकी बोली में अपलोड और वित्तीय बोली से संबंधित वित्तीय बोली में ही अपलोड करने चाहिए ।
- (श) BoQ और वित्तीय बोली को भरने के लिए एनेक्सचर सी वित्तीय बोली प्रारूप में दिए गए है। ई टेंडरिंग पोर्टल वित्तीय निविदा भरने के लिए निर्देश के लिए देखें ।
- स) बोलीदाता को लिए अधिकतम अनुमेय आकार स्थानीय ग्राहक 2 जीबी या अधिक रैम होना चाहिए कि एक शर्त के साथ 20 एमबी 25 एमबी है. बोलीदाताओं ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए न्यूनतम संकल्प में पीडीएफ प्रारूप में दस्तावेज़ को स्कैन करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं।
- (ष) ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के लिए समय 20 मिनट का होगा ।

संयुक्त शासन सचिव कार्मिक (ख) विभाग शासन सचिवालय, जयप्र पंजीयक एनेक्सर-एफ

शासन सचिवालय, जयपुर विषय :- निविदा प्रस्तुत महोदय,

ई-निविदा सूचना क्रमांक 7(04) कार्मिक/ख—3/2017 दिनांक 09/03/2017 के के क्रम में शासन सचिवालय जयपुर के विभिन्न विभागों, अनुभागों, मंत्रीगणों के कार्यालय, आयोग, लोकायुक्त सचिवालय एवं बोर्ड के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 (दिनांक-01.05.2017 से 30.09.2017 तक या कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों पर नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो) में 176 कम्प्यूटर मय दक्ष ऑपरेटर किराये पर लेने के अनुमोदन हेतु अपने अनुबंध (एस) के साथ इस टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप देने, दरों पर वित्तीय निविदा प्रपत्र में उल्लेख किया है, जबिक

1. निम्नलिखित दस्तावेज जमा फीस आदि जमा जाने के सब्त के संबंध में प्रस्त्त किये जाने रहे है:-

क्र0सं0.	विवरण्	नम्बर	दिनांक	बैंक
1.	निविदा श्ल्क: रु. 1000 / -			
	नकद, डीडी / बैंकर चैक ( संयुक्त शासन सचिव,			
	कार्मिक (ख) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर			
	के नाम से बना हो जो जयपुर में देय हो)			
2.	RISL प्रसंस्करण शुल्क: रु. 1000/-			
	डीडी /बैंकर्स चैक (प्रबन्ध निदेशक RISL, के			
	नाम से बना हो जो जयपुर में देय हो)			
3.	बोली प्रतिभूति राशि रु. 1.50 लाख			
	नकद, डीडी / बैकर्स चैक (संयुक्त शासन सचिव,			
	कार्मिक (ख) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर			
	के नाम से बना हो जो जयपुर में देय हो)			

बोलीदाता के हस्ताक्षर	
हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
स्थिति / हस्ताक्षरकर्ता के पोस्ट	
फर्म / एजेंसी का नाम	
दिनांक	

#### राजस्थान सरकार कार्मिक (ख-3) विभाग

क्रमांक - एफ.7(04)/कार्मिक/ख-3/2017

#### ई-निविदा स्चना

शासन सचिवालय जयपुर के विभिन्न विभागो, अनुभागों, मंत्रीगणों के कार्यालय, आयोग, लोकायुक्त सचिवालय एवं बोर्ड के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 (दिनांक-01;05;2017 से 30;09;2017 तक या किनष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों पर नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो) में 176 दक्ष कम्प्यूटर मय दक्ष ऑपरेटर किराये पर लेने हेत् निर्धारित प्रपत्र में E-Procurement प्रक्रिया के तहत केवल

www.eproc.rajasthan.gov.in की ऑन लाईन निविदा के माध्यम से दर संविदा निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है ।

क्र0सं0	विवरण	विस्तृत विवरण
1	कार्य का विवरण	शासन सचिवालय जयपुर के विभिन्न विभागो, अनुभागों, मंत्रीगणों
		के कार्यालय, आयोग, लोकायुक्त सचिवालय एवं बोर्ड के लिए
		वित्तीय वर्ष 2017-18 (दिनांक-01;05;2017 से 30;09;2017 तक या
		कनिष्ठ लिपिको के रिक्त पदों पर नियमित कर्मचारी उपलब्ध
		होने तक जो भी पहले हो) में 176 कम्प्यूटर मय दक्ष ऑपरेटर
		किराये पर लेने हेतु
2	निविदा की अनुमानित लागत	प्रति वर्ष 75.00 लाख रूपये
3	प्रतिभूति बोली राशि	01.50 लाख रुपये संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख) विभाग
		शासन सचिवालय, जयपुर के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट बना ह्आ
		हो ।
4	निविदा प्रपत्र शुल्क	1000.00 रुपये संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख) विभाग शासन
		सचिवालय, जयपुर के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट बना ह्आ हो ।
5	RISL प्रसंस्करण शुल्क	1000.00 रुपये प्रबन्ध निदेशक, RISL, जयपुर के नाम से
		डिमाण्ड ड्राफ्ट बना हुआ हो ।
6	निविदा आमंत्रितकर्ता	संयुक्त शासन सचिव कार्मिक (ख) विभाग, शासन
		सचिवालय, जयपुर
7	निविदा प्रपत्र को अपलोड करने की दिनांक एवं समय	09/03/2017 को सायं 3.00 बजे
8	निविदा प्रपत्र को डाउन लोड करने के शुरू होने का दिनांक	09/03/2017 को सायं 04:00 बजे
	एवं समय	
9	बोली प्रस्तुत प्रारंभ होने की तिथि व समय	09/03/2017 को सायं 6.00 बजे
10	निविदा प्रपत्र डाउनलोड समाप्ति तिथि व समय	08/04/2017 को सायं 06:00 बजे
11	निविदा प्रस्तुत करने के अन्तिम तिथि व समय	09/04/2017 को सायं 4.00 बजे
12	निविदा प्रपत्र शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि के	10/04/2017 को प्रात- 11;00 बजे
	डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने की तिथि व समय	
13	तकनीकी निविदा खुलने की तिथि व समय	10/04/2017 को सायं 3.00 बजे
14	वित्तीय बोली खोलने की तिथि व समय	तकनीकी रूप से योग्य बोली दाताओं को सूचित कर दिया
		जावेगा
15	अनुबंध की अवधि	(दिनांक-01;05;2017 से 30;09;2017 तक या कनिष्ठ लिपिको के
		रिक्त पदों पर नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले
		हो)

#### निविदा की शर्ते :-

- 1. बोली प्रतिभृति राशि के बिना प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- 2. निविदा प्रपत्र, निविदा सूचना से सम्बन्धित नियम, शर्त सम्बन्धी दस्तावेज निर्धारित निविदा शुल्क नकद, वित्तीय सलाहकार, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में कोई भी विक्रेता किसी भी कार्य दिवस को 3.00 बजे तक जमा करवा कर दिनांक 07.04.2017 तक कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते है या विभागीय वेब साईट www.dop.rajasthan.gov.in, सूचना एवं जनसम्पंक विभाग की वेब साईट www.dipr.rajasthan.gov.in, राज्य लोक उपापन पोर्टल (http://sppp.raj.nic.in), www.eproc.rajasthan.gov.in के पोर्टल से भी डाउन लोड किया जा सकता हैं। डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क निविदादाता द्वारा पृथक से ड्राफ्ट संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना होगा। निविदाऐं निर्धारित प्रपत्र में ही ऑनलाईन स्वीकार की जावेगी।
- 3. निविदा के साथ दिनांक 31.12.2016 तक सर्विस टेक्स चुकता प्रमाण पत्र तथा आयकर विभाग द्वारा जारी पैन् नम्बर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्त्त किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

जयपुर,: दिनांक

- 4. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 5. उक्त निविदाओं को आशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कार्मिक (ख) विभाग का होगा।

#### 6. तकनीकी निविदा को स्वीकार किये जाने हेत् अनिवार्य शर्ते:-

- 1. निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि।
- 2. निविदा प्रपत्र नेट से डाउन लोड किये जाने पर निविदा के साथ निविदा प्रपत्र श्ल्क रू. 1000/- डाफ्ट।
- 3. RISL प्रसंस्करण श्ल्क की राशि रू. 1000/- का बैंकर चैक/डिमाण्ड डाफट।
- 4. वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 01;07;2015 के अनुसार राशि रूपये 8500/- प्रति कम्प्यूटर मय ऑपरेटर से अधिक का भगतान नहीं किया जावेगा।

#### 7. तकनीकी निविदा को स्वीकार किये जाने हेत् आवश्यक शर्ते :-

- 1. निविदा के साथ दिनांक 31.12.2016 तक सर्विस कर जमा का प्रमाण पत्र।
- 2. सर्विस कर पंजीयन संख्या का प्रमाण पत्र स्वयं दवारा प्रमाणित।
- 3. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर प्रमाणित प्रति।
- 4. श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति स्वंय द्वारा प्रमाणित।
- 5. श्रम विभाग द्वारा जारी लाइंसेस की प्रति स्वंय द्वारा प्रमाणित।
- 6. तकनीकी निविदा प्रपत्र भरा हुआ तथा सम्बन्धित सभी परिशिष्ट व सभी दस्तावेज स्वयंदवारा प्रमाणित किये होने चाहिया
- 7. फर्म को राजकीय विभागों/निजी संस्थाओं में गत वर्ष का अन्भव होना आवश्यक हैं।
- 8. फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में फर्म की बिक्री/टर्नओवर रू. 20.00 लाख होना आवश्यक है। इस हेतु निविदादाता द्वारा अपने सी.ए. का प्रमाण पत्र जाना आवश्यक हैं।
- 9. फर्म द्वारा 100 रूपये के नोन ज्यूडिशीयल स्टाम पेपर पर ब्लेक लिस्ट (**Black List**) नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

#### 8. तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर ही निविदादाता की वित्तीय निविदा खोली जावेगी।

- 9. फर्म द्वारा सचिवालय परिसर में आदेश के अनुसार तुरन्त उपकरण व ऑपरेटर उपलब्ध करवाने होगें।
- 10. विभाग द्वारा केवल स्थान उपलब्ध कराया जावेगा। उपकरणों के रख रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी।
- 11. मशीने प्रतिदिन प्रात: 9 बजे से सांयकाल 6 बजे तक कार्यरत रहेगी। आवश्यकता होने पर इस अविध को बढाया भी जा सकेगा।
- 12. स्थापित किये जाने वाले सभी उपकरण निविदा के एनक्सर-ई में वर्णित स्तर के अनुरूप स्पेसीफिकेशन होने चाहिए। कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्प्यूटर सिस्टम अनुमोदित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप है। जहां सिस्टम विहित स्पेसीफिकेशन के स्तर के अनुरूप नहीं पाया जायेगा उसे अनुरूप कराया जाएगा।
- 13. उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान एवं बिजली की फीटिंग की व्यवस्था संबंधित विभाग करेंगे। संबंधित विभाग यह सुविधा भी प्रदान करेंगे कि कार्यालय बंद होने के बाद उपकरण ताले में रखे जा सके।
- 14. निविदाकार को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवायें जारी रखनी होगी। प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाले नये टोनर प्रथम बार निविदादाता द्वारा दिया जायेगा, तत्पश्चात विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।
- 15. किसी भी माह में चार कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जावेगा। यह भी पूर्व में सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर-हाजरी के कारण या किसी खराबी के कारण होतो देय राशि में से प्रतिदिन 300/- रूपये की कटौती की जावेगी।
- 16. विशेष परिस्थितियों में संबंधित विभाग इस चार दिन की अविध को बढ़ा सकते है जिसके लिये उसे लिखित में कारण अंकित करने होंगे एवं यदि बढ़ी हुई अविधि में कोई आवश्यक कार्य होगा तो वह निविदादाता को अन्यत्र स्वयं के खर्चे पर करवा कर देना होगा।
- 17. कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संधारित रखने की पूर्ण जिम्मेंदारी निविदादाता की होगी। इसके लिये किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने की संभवाना होगी तो निविदादाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।
- 18. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की नहीं होगी। अतः यदि निविदादाता चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
- 19. कम्प्यूटर सेवाओं के लिये किसी भी प्रकार का अग्रिम का भ्गतान नहीं किया जावेगा।
- 20. निविदा में आमंत्रित दरें 01.05.2017 से 30.09.2017 तक या किनष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों पर नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो की अविध के लिये विधिमान्य होगी, अनुबन्ध को आपसी सहमित के साथ राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम-29 एवं वित्त विभाग की सहमित के अनुसार बढाई जा सकेगी।
- 21. (i) राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में बोली प्रतिभूति की राशि प्रदाय के लिए प्रदत्त मांग का 0.5% होगी और लघु उद्योगों से भिन्न् रूग्ण उद्योगों की दशा में जिनके मामले प्रोद्योगिकी एवं वित्त पुननिर्माण बोर्ड के समक्ष लिम्बत है, यह बोली के मूल्य का 01.00 प्रतिशत (एक प्रतिशत) होगी।
  - (ii) बोली प्रतिभृति के स्थान पर बोली प्रतिभृति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत निकायों, रजिस्टक़त सोसाईटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।

- 22. अनुबन्ध अविध के दौरान मैन विद मशीन की संख्या अनुमानित से कम/अधिक हो सकती है। अनुबन्ध अविध में वृद्धि राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम--29 वित्त विभाग की सहमति के अनुसार की जा सकेगी।
- 23. यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिणाम से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- 24. विशेष परिस्थितियों में राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम-74 के अनुसार कार्य विभाजित किया जा सकेगा।
- 25. राज्य में दिनांक 26.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम-2013 प्रभावशील है। उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम-2013 के नियम उक्त निविदा पर प्रभावशील होगें।
- 26. प्रभावी श्रम कानूनों के तहत प्रावधायी निधि (EPF) एवं बीमा (ESI) और सेवाकर आदि की राशि जमा दिनांक-31.12.2016 तक के चालान की प्रति संलग्न करे, एवं अन्य वित्तीय अथवा कानूनी दायित्व निविदादाता/ठेकेदार के होंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान राज्य सरकार/सचिवालय प्रशासन द्वारा नहीं किया जावेगा। लागु हाने पर इस बाबत निविदादाता द्वारा बिल के साथ गत माह में जमा करायी गई राशि के चालानों की प्रति संलग्न की जायेगी तथा बिल में यह प्रमाण पत्र अंकित किया जावेगा कि प्रावधायी निधि (EPF) एव बीमा (ESI) राशि जमा करवाने के जो चालान संलग्न किये जा रहे में उनमें इस अनुबन्ध के अनतर्गत कार्यरत श्रमकों की राशि सम्मिलित है।
- 27. यदि किसी सक्षम अधिकारी द्वारा न्यूनतम मजदूरी प्रावधायी निधि (EPF) एवं बीमा (ESI) सेवाकर आदि में इस अनुबन्ध की अवधि में दरों में कोई वृद्धि की जाती है तो ठेकेदार/संस्था को इसका भी भुगतान वहन करना होगा और विभाग का इसमें कोई उत्त्दायित्व नहीं होगा।
- 28. निविदा में प्रथम अपीलीय अधिकारी शासन सचिव कार्मिक विभाग एवं दितीय अपील वित्त विभाग होगा।
- 29 समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो (किसी भी प्रकार पक्षकार संबंधित विभाग व ठेकेदारों) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जाएगी।

## 30. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु : -

- (1.) कार्मिक कार्मिक (ख-3) विभाग, शासन सचिवालय, शासन सचिवालय में मैन विद मशीन का कार्य की दर संविदा के लिए निविदा हेतु दरे 01.05.2017 से 30.09.2017 तक 2017 तक (या किनष्ठ लिपिको के रिक्त पदों पर नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो) के लिए अनुमोदन कराने हेतु बोलीदाताओं को वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर प्रस्ताव प्रस्त्तत करना चाहिए. निविदा प्रथम भाग में तकनीकी निविदा प्रस्ताव एवं द्वितीय भाग वित्तीय निविदा प्रस्ताव होगें।
- (2.) बोलीदाताओं ई-निविदा प्रक्रिया को समझने के लिए वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से जाने के लिए और कड़ी "ठेकेदार के लिए मदद", "डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) के बारे में जानकारी", "पूछे जाने वाले प्रश्न" का उल्लेख है और चाहिए "बोलीदाताओं मैन्अल किट 'और वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक बोलियां प्रस्तुत करनी होगी।
- (3.) बोलीदाताओं एक वर्ग 2 या ई निविदा पोर्टल के लिए एक लाइसेंस प्राप्त प्रमाणन प्राधिकरण (सीए) द्वारा जारी वर्ग 3 श्रेणी के डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता है.
- (4.) पूरा बोली दस्तावेज डाउनलोड करने के प्रयोजन के लिए वेबसाइटों http://dop.rajasthan.gov.in और http://eproc.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित किया गया है. दस्तावेज में केवल 1,000 रुपये की बोली दस्तावेज शुल्क के जमा करने के उपरान्त ही डाउनलोड की अंतिम बोली प्रक्रिया के विषय में भाग लेने के लिए वैध माना जाएगा यह राशि नकद जमा करवाई जा सकती है या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के माध्यम से संयुक्त शसन सचिव, कार्मिक (ख) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर के पक्ष में देय हो और ई टेंडर प्रक्रिया शुल्क. 1000 / डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर के प्रबंध निदेशक, RISL, जयपुर के नाम से देय हो संलग्न कर प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
- (5.) बोली दस्तावेज (तकनीकी और वित्तीय बोली) सिहत सभी संचार / पत्राचार बोलीदाता के नामित अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए ।
- (6.) तकनीकी बोली निविदा सूचना में और बोली लगाने के नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा सूचना में अंकित दिनांक के अनुसार खोला जाएगा. तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया की योग्यता प्राप्त बोलियों पर ही वित्तीय निविदा के मूल्यांकन के लिए आगे विचार किया जाएगा. वित्तीय बोली हेतु सभी तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों को बाद में सूचित किया जाएगा जो अलग तारीख और समय पर तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं / नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी।
- (7.) बोलीदाताओं को बोली प्रतिभूति राशि, निविदा शुल्क, और ई-टेंडर प्रक्रिया शुल्क राशि के डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक एवं ई-निविदा प्रपत्र (केवल तकनीकी निविदा) की हार्डकॉफी दिनांक 10/04/2016 को प्रात- 11;00 बजे पंजीयक, शसन सचिवालय, जयप्र के कक्ष में जमा करवानी होगी

- 31. ई-निविदा से संबंधित बिन्दु (1.) बोलीदाता ई उपापन की बेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in को देखें एवं बोली के लिए पंजीकरण और ई निविदा प्रस्तुत करने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा ।
- (2.) बोलीदाताओं बोली प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख के पहले अच्छी तरह से अपनी बोली प्रस्तुत करना चाहिए कार्मिक विभाग आखिरी समय पर प्रस्तुत करने के दौरान बोलीदाता को पेश करने में आ रही किसी भी समस्या के लिए उत्तरदायी नहीं होगा एवं समय सीमा / वेबसाइट पर प्रस्तुत नहीं की बोलियों को शामिल करने के लिए अनुमित का विस्तार से उपरोक्त कारणों की वजह से विचार नहीं किया जाएगा।
- (3.) बोलीदाताओं को बेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in/ पर रजिस्टर और ई-टेंडर के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा । बोली ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी । ऑफ़लाइन प्रस्तुत बोलियों के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया किया जावेगा और खारिज कर दिया जाएगा ।
- (4.) वित्तीय बोली के लिए, बोलीदाताओं बोली के एक भाग के रूप में वेबसाइट पर अपलोड BoQ.XLS (माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ़ाइल) डाउनलोड करना चाहिए और टेम्पलेट के लिए किसी भी संशोधन के बिना विवरण भरें जबकि अपलोड ई) डाउनलोड BoQ.XLS (माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ़ाइल) में किए गए छेड़छाड़ / परिवर्तन प्रारूप वेबसाइट द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
- (5.) बोलीदाता ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक वैध वर्ग 2 या वर्ग 3 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की जरूरत है ।
- (6.) बोलीदाता अपनी बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तृत सभी दस्तावेजों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने आवश्यक है।
- (7.) कामिर्क विभाग गैर अनुपालन के मामले में ई टेंडरिंग प्रक्रिया के लिए बोलियों की अस्वीकृति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- (8.) बोलीदाताओं सभी आवश्यक दस्तावेजों निविदा दस्तावेज में उल्लेख किया है अपलोड करने की जरूरत है ।
- (9.) यदि कोई शुद्धिपत्र वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा और वह इस बोली का एक हिस्सा होगा बोलीदाताओं बोली से संबंधित अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से इस वेबसाइट को देखना चाहिए ।
- (10.) बोलियां को ऑनलाइन खोला जाएगा । बोलीदाता कार्मिक (ख-3) विभाग में बोली ऑन लाईन खोलते समय उपस्थित हो सकते हैं ।
- (11.) बोलीदाताओं को उनकी बोली प्रतिभूतिराशि, निविदा दस्तावेज शुल्क और ई टेंडर प्रक्रिया शुल्क प्रस्त्त करना चाहिए।
- (12.) बोलीदाताओं को दस्तावेज अपलोड करते समय सावधान रहना चाहिए । तकनीकी बोली से संबंधित दस्तावेज केवल तकनीकी बोली में अपलोड और वित्तीय बोली से संबंधित वित्तीय बोली में ही अपलोड करने चाहिए ।
- (13.) BoQ और वित्तीय बोली को भरने के लिए एनेक्सचर सी वित्तीय बोली प्रारूप में दिए गए ई टेंडरिंग पोर्टल में वित्तीय निविदा भरने के लिए निर्देश के लिए देखें ।
- (14.) बोलीदाता के लिए अधिकतम अनुमेय आकार स्थानीय ग्राहक 2 जीबी या अधिक रैम होना चाहिए कि एक शर्त के साथ 20 एमबी 25 एमबी है. बोलीदाताओं ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए न्यूनतम संकल्प में पीडीएफ प्रारूप में दस्तावेज़ को स्कैन करने के लिए अन्रोध कर रहे हैं।
- (15.) ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के लिए समय 20 मिनट का होगा ।
- 32. निविदा शुल्क, RISL प्रसंस्करण शुल्क व बोली प्रतिभूति राशि के बैकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट एनेक्सर-आई में अलग से प्रस्तुत किये जावे।

संयुक्त शासन सचिव कार्मिक (ख) विभाग शासन सचिवालय, जयप्र

#### निविदा की आवश्यक शर्तें

- अनुबंध प्रारम्भ में 01.05.2017 से 30.09.2017 तक की अविध के लिए होगा एंव संतोषप्रद कार्य करने पर उसे RTPP. नियम-29 के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा। वित्त विभाग द्वारा अभी किराये के दक्ष कम्प्यूटर मय दक्ष ऑपरेटर हेतु अधिकतम निर्धारित राशि रूपये 8500.00 प्रति कम्प्यूटर मय ऑपरेटर प्रतिमाह है इससे अधिक का भ्गतान नहीं किया जावेगा।
- 2. स्थापित किये जाने वाले सभी उपकरण निविदा में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिए। कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्प्यूटर सिस्टम अनुमोदित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप है। जहां सिस्टम विहित स्पेसीफिकेशन के स्तर में अनुरूप नहीं पाया जायेगा, उसे अनुरूप कराया जाएगा।
- 3. उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान एंव बिजली की फीटिंग की व्यवस्था संबंधित विभाग करेंगे। संबंधित विभाग यह स्विधा भी प्रदान करेंगे कि कार्यालय बंद होने के बाद उपकरण ताले में रखे जा सके।
- 4. निविदाकार को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवायें जारी रखनी होगी। प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाले नया टोनर / नया रिबन प्रथम बार निविदादाता द्वारा दिया जायेगा, तत्पश्चात विभाग दवारा वहन किया जायेगा।
- 5. किसी भी माह में चार कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जायेगा। यह भी पूर्व में सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इसे अधिक समय तक कप्यूटर बंद रहने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजिरी के कारण या किसी खराबी के कारण हो तो देय राशि में से प्रतिदिन 300/- रूपये की कटौति की जावेगी।
- 6. विशेष परिस्थितियों में संबंधित विभाग इस चार दिन की अवधि को बढ़ा सकते है जिसके लिये उसे लिखित में कारण अंकित करने होंगे एंव यदि बढ़ी हुई अवधि में कोई आवश्यक कार्य होगा तो वह निविदादाता को अन्यत्र स्वयं के खर्च पर करवा कर देना होगा।
- 7. कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संधारित रखने की पूर्ण जिम्मेंदारी निविदादाता की होगी। इसके लिए किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने की संभावना होगी तो निविदादाता को तब तक अन्य व्यवस्था करनी होगी।
- 8. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की नहीं होगी। अतः यदि निविदादाता चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
- 9. कम्प्यूटर सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम का भ्गतान नहीं किया जायेगा।
- 10. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर ऑनलाईन बैंक अकाउन्ट में किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जायेगा।
- 11. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी प्रकार पक्षकार (संबंधित विभाग व ठेकेदारों) दवारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही पेश किया जायेगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जायेगी।(
- 12. प्रभावी श्रम कानूनों के तहत प्रावधायी निधि (EPF) एंव बीमा (ESI) और सेवाकर आदि की राशि जमा करवाने, एंव अन्य वित्तीय अथवा कानूनी दायित्व निविदादाता/ठेंकेदार के होंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान राज्य सरकार/सचिवालय प्रशासन द्वारा नहीं किया जावेगा। लागु होने पर इस बाबत निविदादाता द्वारा बिल के साथ गत माह में जमा करायी गई राशि के चालानों के प्रति संलग्न की जायेगी तथा बिल के साथ गत माह में जमा करायी गई राशि के चालानों के प्रति संलग्न की जायेगी तथा बिल में यह प्रमाण पत्र अंकित किया जावेगा की प्रावधायी निधि (EPF) एंव बीमा (ESI) राशि जमा करवाने के जो चालान संलग्न किये जा रहे हैं में उनमें इस अनुबंध के अनतर्गत कार्यरत श्रमिकों की राशि सम्मिलित है।

- 13. यदि किसी सक्षम अधिकारी द्वारा न्यूनतम मजदूरी प्रावधायी निधि (EPF) एंव बीमा (ESI) सेवाकर आदि में इस अनुबंध की अविध में दरों में कोई वृद्धि की जाती है तो ठेकेदार/संस्था को इसका भी भुगतान वहन करना होगा और विभाग का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 14. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहाँ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियमों, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम -2012 व नियम-2013 तथा वित्त(बजट) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 28.07.2008, 25.07.2011, 01.05.2014 व 01.07.2015 के प्रावधान लागू होंगे।

निविदा दाता का नाम मय हस्ताक्षर एवं	
मोहर	
दिनांक	
निविदादाता/संस्था का नाम एवं फर्म की	
मोहर	
संस्था की स्थिती में हस्ताक्षर करने वाले	
का नाम व पदनाम एवं प्रमाणित हस्ताक्षर	
फोन नं.	
मोबाईल नं.	

# Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the
- not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation; (c)
- not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

disclose conflict of interest, if any; and (g)

disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country (h) during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

#### Conflict of Interest: -

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the
- the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject
- Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract. Docl



# Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

#### Declaration by the Bidder

- 1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
- I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
- I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our
  affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities
  suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
- 4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
- I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

Docl

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is 4 344 0 21141 11179 118 The designation and address of the Second Appellate Authority is

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

#### (4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following

(a) determination of need of procurement;

- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) cancellation of a procurement process;

(e) applicability of the provisions of confidentiality

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee. Docl



(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.
- (7) Procedure for disposal of appeal
- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

- (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public

Docl

FORM No. 1 Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement [See rule 83] Act, 2012 Appeal No .....of ..... (i) Name of the appellant: (ii) Official address, if any: (iii) Residential address: 2. Name and address of the respondent(s): (i) (iii) 3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved: 4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative: 5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal: Grounds ..... (Supported by an affidavit)

Docl

Appellant's Signature

# Annexure D: Additional Conditions of Contract

## 1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

# 2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the

Doc1

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

# राजस्थान सरकार कार्मिक (ख–3) विभाग

क्रमांकः प. 7(04) कार्मिक / ख-3 / 2017

जयपुर, दिनांक : -

निदेशक,

जन-सम्पर्क निदेशालय,जयपुर।

विषय:- निविदा प्रकाशित कराए जाने बाबत्।

महोदय,

निर्देशानुसार अनुरोध है कि संलग्न निविदा सूचना को नियमानुसार पचास हजार प्रतियों और उससे अधिक का परिचालन रखने वाला एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार—पत्र व एक अखिल भारतीय स्तर का अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 10.03..2017 से पूर्व प्रकाशित करवाकर प्रकाशित समाचार पत्रों की एक प्रति इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें, साथ ही निविदा सूचना को वेब साईट पर प्रकाशन हेतु सॉफ्ट कॉपी भी संलग्न कर भेजी जा रही है।

संलग्न : दो प्रतियाँ एवं सॉफ्ट कॉपी।

भवदीय.

संयुक्त शासन सचिव कार्मिक (ख) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।

# प्रतिलिपि :-

- 1. अवधाता, शासन सचिवालय, जयपुर को नोटिस बोर्ड पर लगाए जाने हेतु प्रेषित है।
- 2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक, कम्प्यूटर) कार्मिक विभाग को विभागीय वेबसाईट पर निविदा सूचना, निविदा प्रपत्र एवं शर्तो को प्रकाशित किए जाने हेतु dopcomputer@yahoo.co.in पर भेज दिया गया है।
- 3. राज्य लोक उपापन पोर्टल (http://sppp.raj.nic.in) पर निविदा सूचना,निविदा प्रपत्र एवं शर्तों के प्रकाशित किए जाने हेत् मय सॉफट कॉपी में प्रेषित है।

पंजीयक शासन सचिवालय जयपुर